Report of Refree about Durand Semi-Final Match

2429. SHRI AJIT BAG: Will the Minister of SPORTS be pleased to state:

(a) what was the report of the referee submitted to the Durand Committee about the semi-final match of East Bengal and JCT Mills on 7 February, 1983;

(b) the reasons for not accepting the report;

(c) was it not preplanned; and

(d) if not, the findings of the Government?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) The substance of the refree's report to the Secretary, Durand Football Tournament was that he was forced to abandon the match in the 13th minute of the second half due to the invading of the playing field by a mob of spectators—some of them assaulting the referee and other sports officials supervising the game.

(b) and (c). The Durand Football Tournament Committee has stated that the report submitted by the referee was accepted by the tournament authorities and that the disturbance was not preplanned.

(d) Government is not concerned with the conduct of the tournament.

Proposals for Utilisations of Asiad Facilities

2430. SHRI MADAVRAO SCINDIA: Will the Minister of SPORTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government have received a number of proposals for the future utilisation of Asiad facilities; and

(b) if so, the details thereof and the Governments reaction in that regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The suggestions include utilisation of the facilities through a company or a society. The Government agree that satisfactory arrangements have to be made for the proper future use of the facilities.

Unauthorised Construction of Third Storeys by Allottees of DDA (LIG) Flats in Rajouri Garden

2431. SHRI T. M. SAWANT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some allottees of DDA (LIG) flats in Rajouri Garden (double storeys) have constructed another unit as third storey at the terrace without the permission from the authorities concerned;

(b) if so, whether the structure of the said flats was primarily constructed for double storeys only;

(c) if so, whether Government propose to demolish the un-authorised units constructed at the terrace in near future; and

(d) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The DDA has reported that whenever such cases are detected, notices are issued and action under Section 30 of the Delhi Development Act, 1957 initiated. Orders of demolition are passed after completion of these formalities.

दिल्ली दुग्ध योजना की दुग्ध वितरण प्रणाली

2432. श्री त्रिलोक चन्द :

श्री के० ए० राजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध वितरण प्रणाली किस प्रकार से क्रियान्वित की है ;

(ख) क्या टोकन प्रणाली जो पहले लागू थी समाप्त कर दी गई है और क्या इस प्रणाली को पुनः लागू करने हेतु आवेदन पत्र फार्म के लिये शुल्क निर्धारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं की बूथवार संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार को इन आवेदन पत्र फार्मों की बिक्री से कुल कितनी आय होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर अपने डिपुओं से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को दूध की सप्लाई कर रहा है । इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को उनके घरों में प्राधिकृत "होम डिलिवरी एजेंसी" द्वारा भी दूध का वितरण किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). टोकन पद्धति को चरणों में हटाने का कार्य फरवरी, 1980 में पूरा हो गया था । दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की अत्यधिक मांग को देखते हुए कुछ इलाकों में परीक्षण के तौर पर टोकन पद्धति को पुनः शुरू करने का निर्णय किया गया है । इच्छुक आवेदनकर्ताओं को लगभग 40,000 आवेदन पत्र फार्म निशुल्क उपलब्ध कराए गये ।

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित हुए गांव

2433. **श्री कुवंर राम :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे गांवों को 20 सूत्री कार्यक्रम से किस हद तक लाभ पहुंचा है ; और

(ख) ऐसे गांवों की जिलावार संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) इस मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जोकि नए बीस सूत्री कार्यक्रम के मद संख्या 3 व 4 में भी शामिल किये गये हैं, के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :—

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1980–81, 1981–82 तथा 1982–83 के दौरान बिहार में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत लाभभोगियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1980–81	2,52,630
1981–82	2,76,169
1982–83 (जनवरी 1983 तक)	1,21,159

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र में केवल राज्यवार सूचना संकलित की जा रही है । बिहार में 1980–81, 1981–82 तथा 1982–83 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार निम्न प्रकार है :—

1980–81	343.96 लाख श्रम दिन
1981–82	318.70 लाख श्रम दिन
1982–83 (जनवरी 1983 तक)	271.72 लाख श्रम दिन

भूमि सुधार

भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी केन्द्र में केवल राज्यवार सूचना संकलित की जा रही है । वर्ष 1980 से